

कपिल मिश्रा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का निचली अदालत से अनुरोध

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत से सुनवाई टालने का अनुरोध किया है। यह मामला 2020 के विधायक सभा चुनावों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेगा ने निदेश तब दिया जब मिश्रा के वर्षीय, मध्ये जेमलानी, ने कोर्ट को जानकारी पढ़ी तो दिल्ली पुलिस ने अपने पूरक आरोपत्र में कुछ ऐसी फाइल शामिल की है, जो एक्स-पूर्व मेंटरिकोर्ट से मिली थी। जेमलानी के अनुसार, ये फाइल कोर्टिंग और पठन योग्य नहीं थीं। मिश्रा के वर्षीय जेमलानी ने कोर्ट से निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग कर तरफ दिया कि दसवारों को एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराए कि कार्यवाही शुरू करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपर द्वायल कोटी आगे बढ़ता है, तब उनकी अपील निरर्थक होगी। कोर्ट ने इन दीलों को स्वीकार करते हुए निचली अदालत से सुनवाई को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई आती तारीख तक स्थगित करने का अनुरोध किया। अब यह मामले की ओर नियमांश 13 अक्टूबर को होगी। इस मामले का एक दूसरा नियमांश 24 जुलाई 2020 को दर्ज हुई एक एक्स-इंडियार द्वारा आया था, जिसमें कपिल मिश्रा पर संशेष योग्यता पर भड़काऊ समीक्षा प्रोसेस करके आदर्श आचार संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिकारियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

महां मोदीता का विवादित बयान, शाह का सिर काटने की बात कही

कोलकाता (एजेंसी)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस संसद महूआ मोदीता विवादों में फिर गई है। भरतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि मोदीता ने शाह का सिर काटने की बात कही है। खास बात है कि यह मामला तब सामने आया है, जब बिहार में प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ रहा है। बंगाल भाजपा ने खिलाफ, जहां मोदी गृहमंत्री का सिर काटने की बात कही है, तब ये टीएमपी की निराशा और हिंसा की संरक्षित को दिखाता है, जो बंगाल की छिपे खराब कर रही है और राज्य का पीछे ले जा रही है। पार्टी ने वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें मोदीता प्रकारों से बालीती करते दिख रहे हैं।

पंजाब में 37 साल में पहली बार भीषण बाढ़, कई जिले पूरी तरह जलमग्न

-एनआरआई पंजाबियों ने बढ़ाया नदद का हाथ
अमृतसर (एजेंसी)। पंजाब में 37 साल में पहली बार भीषण बाढ़ आई, जिसने 1988 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिमावत प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण रुद्रगंग, यास और रावी नदियों उपर हैं, जिससे पंजाब के कई जिले तूरह तरह प्रभावित हुए हैं। पंजाब के प्रभावित क्षेत्र में पांचनाटक, गुरदासपुर, फाजिलपा, तरनतारन, कपूरथला, फिरेजपुर, होशियारपुर, और अमृतसर जैसे जिलों में हालत गंभीर है। सैकड़ों गाँव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है, और मामला तूल पकड़ रहा है। लोग आपने घरों और पशुओं को छोड़कर अतिरिक्त शिविरों में रहने को मजबूर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ का कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। चींगड़ में एक उच्च-स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है। राजपुर में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष और अपातकानीन ब्लैप्पलन नंबर रखा गया है। विदेशों में रहने वाले पंजाबी समुदाय ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। संशेष मीडिया पर सप्ते फार पंजाब टैट कर रहा है। यह बाढ़ पंजाब के लिए एक बड़ी चुनौती है, और सरकार के साथ-साथ आम लोग भी इस आपात से निपटने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं।

झारखंड के दो मंत्रियों की हत्या की धमकी...युवक पटना से गिरपतार

रंगी (एजेंसी)। झारखंड के गिरिही बुलिस की विशेष जांच टीम (एसआई) ने 21 वीर्युग्र युवक को गिरपतार किया है, युवक ने वीडियो में झारखंड के दो मंत्रियों की हत्या की धमकी दी थी। राजेंद्र नारान निवारी आरोपी अविळ कमर मिश्रा को पटना में गिरपतार किया। मिश्रा ने वीडियो में दाव किया था कि उसके पैरस्टर रुद्रपुर से विशेषज्ञ नई एसआई बुलिस अधिकारी (एसआई) ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपने एवं वीडियो में मिश्रा ने गिरिही विधायक सुविधा को खुलासा की गयी और राज्यस्थ मीर इरफान अंसारी को 24 घंटे के भीतर जान से मारने की धमकी दी। कुमार ने कहा, मिश्रीही के हिसाब से खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद एसआई का गठन किया। एसआई ने वीडियो की ओर खासकर पिछों के लिए जेल जा रहा है। पुलिस ने बायाका कि मिश्रा के खिलाफ धमकी दी देने और अशायिया फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया जाएगा।

हिमाचल, उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर में जल बहाल होनी गोबाइल सेवाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंहिया ने बहुत संतानों के बाद ग्रामीण और जम्मू-कश्मीर के बाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संरचनाएं सेवा बहाल करने के संबंध में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अधिकाकाता की। इस बैठक में साचाव (दूरसंचार) डॉ. नीरज मित्रल, संचार मंत्री, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसपीएल) और अन्य दूरसंचार संसाधारों के विकास की ओर संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास की विदेश नीति में एक साथ अहम विप्रवाचन बैठक हो रही है। यह भारत की विदेश नीति में एक संतुलनकारी कदम है, खासकर अमेरिका के द्वाये प्रशासन से बहुत अधिक और कूटनीतिक तनाव के कारण ऐसी परिस्थिति बनी है। वहां इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर बीड़ी है। मजबूर बात ये है कि अंतर्जाल के लिए तकाल युद्धस्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अंतर-जांच और धारी संरचनाएं की प्रतीक्षाएं पर भी कठीन रही हैं। ये दोनों देशों के विदेशी अधिकारियों के बीच विवाद की ओर साथ आया है।

कब भरी जाएंगी 2021 से खाली जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटें?

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें फरवरी 2021 से रिकॉर्ड पड़ी हैं। चुनाव आयोग ने केंद्र से अनुरोध किया था कि ग्रामीण योग्यता द्वारा सभी चार रिकॉर्ड पड़ी ग्रामीण सभी सीटों का कार्यकाल अलग-अलग यानी स्ट्रेंगर टार्म्स के लिए निर्धारित बनी थीं (जैसे पंजाब और दिल्ली)। ऐसा नामांत्रण स्विधान संसोधन के बिना नहीं थी।

जम्मू-कश्मीर की नई अदालत से अनुरोध किया गया था कि दसवारों को एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराए कि कार्यवाही शुरू करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपर द्वायल कोटी आगे बढ़ता है, तब उनकी अपील निरर्थक होगी। कोर्ट ने इन दीलों को सिविल अदालत से सुनवाई की दिल्ली नहीं थी।

आयोग ने कहा कि यह साथी का कार्यवाही शुरू करना संभव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर की नई अदालत से अनुरोध किया गया था कि दसवारों को एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराए कि दसवारों को एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराए कि कार्यवाही शुरू करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपर द्वायल कोटी आगे बढ़ता है, तब उनकी अपील निरर्थक होगी। कोर्ट ने इन दीलों को सिविल अदालत से सुनवाई की दिल्ली नहीं थी।

आयोग ने कहा कि यह साथी का कार्यवाही शुरू करना संभव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर की नई अदालत से अनुरोध किया गया था कि दसवारों को एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराए कि कार्यवाही शुरू करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपर द्वायल कोटी आगे बढ़ता है, तब उनकी अपील निरर्थक होगी। कोर्ट ने इन दीलों को सिविल अदालत से सुनवाई की दिल्ली नहीं थी।

आयोग ने कहा कि यह साथी का कार्यवाही शुरू करना संभव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर की नई अदालत से अनुरोध किया गया था कि दसवारों को एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराए कि कार्यवाही शुरू करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपर द्वायल कोटी आगे बढ़ता है, तब उनकी अपील निरर्थक होगी। कोर्ट ने इन दीलों को सिविल अदालत से सुनवाई की दिल्ली नहीं थी।

आयोग ने कहा कि यह साथी का कार्यवाही शुरू करना संभव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर की नई अदालत से अनुरोध किया गया था कि दसवारों को एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराए कि कार्यवाही शुरू करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपर द्वायल कोटी आगे बढ़ता है, तब उनकी अपील निरर्थक होगी। कोर्ट ने इन दीलों को सिविल अदालत से सुनवाई की दिल्ली नहीं थी।

आयोग ने कहा कि यह साथी का कार्यवाही शुरू करना संभव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर की नई अदालत से अनुरोध किया गया था कि दसवारों को एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराए कि कार्यवाही शुरू करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपर द्वायल कोटी आगे बढ़ता है, तब उनकी अपील निरर्थक होगी। कोर्ट ने इन दीलों को सिविल अदालत से सुनवाई की दिल्ली नहीं थी।

आयोग ने कहा कि यह साथी का कार्यवाही शुरू करना संभव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर की नई अदालत से अनुरोध किया गया था कि दसवारों को एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराए कि कार्यवाही शुरू करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपर द्वायल कोटी आगे बढ़ता है, तब

